an>

Title: Regarding procurement of rice at minimum support price in Diglipur and Rangat Tehsil in Andaman and Nicobar Islands.

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): सभापति महोदय, भारत सरकार कहती है कि किसान का धान एवं चावल समर्थन मूल्य में खरीदेंगे, लेकिन अंडमान-निकोबार के साथ में ये सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। यहां पवन कुमार बंसल जी बैठे हैं, कृपा कर वे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारे अंडमान में मुख्य मंत्री नहीं है, सरकार के प्रधान मंत्री ही वहां के मुख्य मंत्री हैं, आप सरकार में हैं। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में आज किसानों की हालत क्या है, किसान जो धान एवं चावल पैदा करता है, डिग्लीपुर तहसील में गांधीनगर, गणेशनगर, शांतिनगर, तालबगान, राधानगर, रंगत तहसील में किसान मजबूरी में अपने चावल को सात से आठ रुपए किलो में बिक्री कर रहा है। भारत सरकार का मिनिमम सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य एक हजार रुपए प्रति-क्विंटल धान के लिए तय किया गया है। इसका मतलब एक किलो चावल की कीमत 16 से 18 रुपए हुई, लेकिन अंडमान-निकोबार इस कीमत पर नहीं खरीद रहा है। अगर अतीत में जाएं, जब मैं सन् 2001 से 2004 तक सांसद था तो भारत सरकार ने किसानों से चावल खरीदा था, कॉमन वेरायटी और ग्रेड वन वेरायटी खरीदने का तरीका बनाया था। फूड कार्पोरेशन इंडिया के साथ में लोकल डिपार्टमेंट सिविल सप्लाई, कृषि विभाग एवं फोरेस्ट कार्पोरेशन विभाग के माध्यम से बढ़िया क्वालिटी का दो किस्म का चावल खरीदा गया था - कॉमन वेरायटी और ग्रेड वन तथा पीडीएस के माध्यम से एफसीआई के थ्रु सप्लाई किया था। उस समय किसी की कोई कम्प्लेंट भी नहीं आई थी।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने पिछले साल मांग की थी, लेकिन सरकार ने नहीं खरीदा। मैंने फिर दोबारा 22 जनवरी को उपराज्यपाल महोदय को मांग की और उन्हें पत्र भी भेजा। मैंने मांग की कि अंडमान के किसानों के पास जो चावल एवं धान पड़ा है, वह समर्थन मूल्य से खरीदा जाए। उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में चावल चेन्नई और आंध्र प्रदेश से आता है और वहां से एफसीआई वाले लाते हैं। वह चावल जब अंडमान में पहुंचता है तो वहां एक किलो चावल की कीमत कम से कम तीस रुपए पड़ती है। जब वही चावल अंडमान-निकोबार में 16 एवं 18 रुपए किलो में सरकार समर्थन मूल्य से खरीदेगी और किसान बेचेगा तो सरकार को वह चावल 18 रुपए में मिलेगा। इससे सरकार को रुपए की बचत भी होगी और किसानों में आर्थिक मजबूती भी आएगी। यह चावल एफसीआई द्वारा राशन की दुकानों के माध्यम से कार्ड होल्डर को दिया जाए।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार अंडमान-निकोबार के साथ में सौतेला व्यवहार न करे, किसान को बचाए। किसानों का जो धान एवं चावल है, सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है, सरकार उसी मुताबिक खरीदे।

सभापति महोदय, मैं पुन: आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस पर सरकार कार्यवाही करे। जयहिन्द।